

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 फरवरी 2011—माघ 22, शक 1932

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2011

क्रमांक एफ 50/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/10/210.—दिनांक 3 फरवरी 2011 को नगर पालिक निगम चिरमिरी, जिला-कोरिया के 01 अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. के. तिवारी,
उप सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-50/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

अमरजीत प्रसाद, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पालिक निगम, चिरमिरी, जिला-कोरिया, छ. ग.

आदेश

(छ. ग. नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-ख के अन्तर्गत)

पारित दिनांक 03 फरवरी, 2011

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) कोरिया के प्रतिवेदन दिनांक 2 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-ख के तहत प्रारंभ किया गया है।
2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पालिक निगम, चिरमिरी के महापौर पद के लिये आम निर्वाचन में कुल 6 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था। निर्वाचन परिणाम 27 दिसम्बर 2009 को घोषित किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) कोरिया ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 2 फरवरी 2010 के साथ निर्धारित प्रपत्र में जानकारी संलग्न कर प्रतिवेदित किया है कि नगर पालिक निगम, चिरमिरी के आम निर्वाचन 2009 में लड़ने वाले अभ्यर्थियों में से अमरजीत प्रसाद द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् 30 दिवस के अंदर अर्थात् दिनांक 27 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) कोरिया के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाले उपरोक्त अभ्यर्थी को कारण बताओ सूचना दिनांक 12 मार्च 2010 को जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में चाहा गया। कारण बताओ सूचना उपरोक्त अभ्यर्थी को दिनांक 28 मई 2010 को सम्यक् रूप से तामील किया गया है। कारण बताओ सूचना उपरोक्त अभ्यर्थी अमरजीत प्रसाद को विधिवत् तामील होने के उपरान्त भी उनके द्वारा अपना जवाब न तो निर्धारित समयावधि में और न ही उसके पश्चात् आज पर्यन्त प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि उपरोक्त अभ्यर्थी को अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।
4. प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का परिशीलन किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) कोरिया ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी अमरजीत प्रसाद ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है। यह अधिनियम की धारा 14-क (1) एवं 14-ख का उल्लंघन है। अधिनियम की धारा 14-क (1) निम्नानुसार है :

“14-क. निर्वाचन व्ययों का लेखा—(1) महापौर के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा।”

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 14-क (1) की अपेक्षानुसार महापौर पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 14-ख निम्नानुसार है :

“धारा 14-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना—महापौर के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 14-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा।”

अधिनियम की धारा 14-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से तीस दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है। निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं

प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्यिष्ट किया गया है। अतः उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाना था। उक्त जानकारी 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था।

5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) कोरिया के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पालिक निगम चिरमिरी के महापौर पद के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अमरजीत प्रसाद द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा अधिनियम की धारा 14-क (1) तथा धारा 14-ख की अपेक्षानुसार अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना का कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दिया। अतः मुझे यह समाधान हो गया है अभ्यर्थी अमरजीत प्रसाद प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहा है तथा उक्त अभ्यर्थी इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखता है। तदनुसार अधिनियम की धारा 14-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थी अमरजीत प्रसाद को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 14-ग (ख) में वर्णित कोई न्यायोचित्य नहीं रखने के कारण उन्हें इस आदेश की तारीख से चार वर्ष सात माह की कालावधि के लिये नगर पालिक निगम के महापौर होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है। अधिनियम की धारा 14-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए।

6. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 03 फरवरी 2011 को जारी किया गया।

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)

राज्य निर्वाचन आयुक्त.

